



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श10)

(सं0 पटना 617) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 मई 2017

सं० 22/नि०सि०(औ०)-17-07/2007-707—श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी (आई०डी०-3531) तत्कालीन सहायक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल सं०-2, औरंगाबाद के विरुद्ध मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के अवासीय परिसर में जीप शेड, चौकीदारी शेड तथा प्रमण्डलीय कार्यालय भवन की मरम्मत कार्य में बरती गई अनियमितताओं एवं अन्य आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-1 सहपठित ज्ञापांक-25, दिनांक 01.02.2005 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 187, दिनांक 03.03.2005 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 121, दिनांक 29.01.2008 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री केसरी से प्राप्त प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इसे पूर्णतया असंतोषजनक पाते हुए विभागीय आदेश सं०-94, सहपठित ज्ञापांक 703, दिनांक 26.08.2008 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गया :-

(i) "निन्दन" वर्ष 2003-04

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक

(iii) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

विभागीय दण्डादेश के विरुद्ध श्री केसरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-16562/2008 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना, द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पारित आदेश में कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी से असहमति के बिन्दुओं पर श्री केसरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई किन्तु असहमति के बिन्दुओं के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं इसे अस्वीकार योग्य पाया गया। विभागीय समीक्षा में श्री केसरी के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को किस आधार पर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया इसका उल्लेख विभागीय समीक्षा में

नहीं है। मात्र मुख्य अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर श्री केसरी के विरुद्ध दण्डादेश निर्गत किया गया है जो कानून की दृष्टि में ग्राह्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश में यह भी अंकित किया गया है कि निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में आरोपित पदाधिकारी को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है जो स्थापित नियमों के विरुद्ध है। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री केसरी को संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए विभाग को नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल सं०-2, औरंगाबाद के विरुद्ध संसूचित विभागीय दण्डादेश सं०-94 सहपठित ज्ञापांक 703, दिनांक 26.08.2008 के निम्न अंश को निरस्त किया जाता है :-

- (i) "निन्दन" वर्ष 2003-04
- (ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक
- (iii) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल सं०-2 के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 187, दिनांक 03.03.2005 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में नए सिरे से विचार कर अलग से निर्णय लिया जा रहा है।

(3) उक्त निर्णय श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल सं०-2 सम्प्रति सहायक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, सहरसा (विकास भवन) को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 617-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>